



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 8 सितम्बर, 2005/17 भाद्रपद, 1927

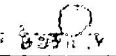
हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 8 सितम्बर, 2005

संख्या एल०एल०आर०डी०(६)-२९/२००५-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक ०६-०९-२००५ को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, २००५ (२००५



का विधेयक संख्यांक 15) को वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 26 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित,
प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

2005 का अधिनियम संख्यांक 26

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन)
अधिनियम, 2005

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 6 सितम्बर, 2005 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम,
2005 (2005 का 14) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2005 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 21 जून, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2005 का 14. 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 5 में उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार—

(क) मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे को कम करने और उसके पश्चात् अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए;

(ख) राजकोषीय घाटे को, कुल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाने हेतु, उत्तरोत्तर कम करने के लिए; और

(ग) दीर्घकालिक ऋण पर इसकी परादेय प्रत्याभूतियों को उत्तरोत्तर कम करने के लिए, जब तक कि यह परादेय जोखिम भारित प्रत्याभूतियों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के अस्सी प्रतिशत तक समाप्त न

कर दें, जिस के लिए वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक उपलब्ध है,

प्रयास करेगी।”।

धारा 6 का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) सरकारी, पब्लिक सैक्टर और सहबद्ध संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या और सम्बन्धित वेतन के ब्यौरे।”।

धारा 8 का
संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए उपाय;
- (ख) धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन राजकोषीय सूचक;
- (ग) धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान का स्वरूप;
- (घ) धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रकटीकरण के लिए विवरणों का स्वरूप; और
- (ङ) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन रिपोर्ट का स्वरूप।”।

2005 के
अध्यादेश
संख्यांक 4
का निरसन
और

5. (1) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

Act No. 26 of 2005.

**THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND
BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2005**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 6TH SEPTEMBER, 2005)

AN

ACT

*to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget
Management Act, 2005 (Act No. 14 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Fiscal
Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2005.

Short title
and
commence-
ment.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of
June, 2005.

4 of 2005 2. In section 5 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility
and Budget Management Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal
Act'), for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

Amend-
ment of
section 5.

“(1) In particular and without prejudice to the generality of the
foregoing provisions, the State Government shall endeavour
to—

- (a) reduce revenue deficit every financial year
compared to previous financial year to eliminate
revenue deficit by March, 2009 and generate revenue
surplus thereafter;
- (b) progressively reduce fiscal deficit to bring it to three
percent of Gross State Domestic Product; and
- (c) progressively reduce its outstanding guarantees on
long term debt, until it can cap outstanding risk
weighted guarantees at eighty percent of total revenue
receipt in the preceding financial year for which
actuals are available as per finance accounts.”.

Amendment
of section 6.

3. In section 6 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(c) the details of number of employees in Government, Public Sector and Allied Institutions and related salaries.”.

Amendment
of section 8.

4. In section 8 of the principal Act, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the measures for evaluation of the fiscal position of the State Government under clause (f) of section 2;

(b) the fiscal indicators under sub-section (2) of section 3;

(c) the form of medium term fiscal plan under sub-section (4) of section 3;

(d) the form of statements for disclosure under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 6; and

(e) the form of review report under sub-section (1) of section 7.”.

Repeal of
Ordinance
No. 4 of
2005 and
savings.

5. (1) The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.